



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार, 20 सितम्बर, 2007 / 29 भाद्रपद, 1929

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अगस्त, 2007.

संख्या:गृह-सी(ए)3-5/2006-11.- हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, में निदेशक वर्ग-1(राजपत्रित) पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, में निदेशक वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं।

(2). ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां :- (1) अधिसूचना संख्या:गृह ए/बीद्ध 2-1/89 तारीख 8.5.1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला सहायक निदेशक, वर्ग-1 (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाही इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,  
एस0 विजय कुमार,  
प्रधान सचिव।

#### उपाबन्ध— “क”

हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में निदेशक वर्ग— I(राजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम : निदेशक
2. पदों की संख्या : 01 (एक)
3. वर्गीकरण : वर्ग— I(राजपत्रित)
4. वेतनमान : 14,300—400—15,900—450—18,600 रुपए।
5. चयन पद अथवा अचयन पद : चयन।
6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा/अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश/(आदर्शों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेदन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी।

जो पश्चात्पूर्वी ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद/(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को

अधिसूचित किया गया है।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

## 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं:-

(क) अनिवार्य अर्हता :- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान (कैमिस्ट्री) प्राणी विज्ञान (जूलॉजी)/वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) /मानव शरीर विज्ञान (फिजिकल ऐन्थ्रोपोलॉजी) /बायो प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी)/जीव रसायन (बायोकैमिस्ट्री)/भौतिक विज्ञान (फिजीक्स)/न्यायालयिक विज्ञान (फॉरेंसिक साइंस/गणित फार्मेसी/अणविक जीव विज्ञान(मालीक्यूलर बायलॉजी)/मानव जीवन विज्ञान(ह्यूमन बायलॉजी)/सूक्ष्म जीव विज्ञान (माइक्रो बायलॉजी)/मानव आनुवंशिकी (ह्यूमन जैनेटिक्स)/भैषजगुण विज्ञान (फार्माकोलॉजी) में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर की उपाधि या इसके समकक्ष।

(ii) उपरोक्त या सहबद्ध किसी एक विषय में शोध प्रशिक्षण और विश्लेषणात्मक कार्य में विज्ञान स्नातकोत्तर (एम0एस0सी0) के उपरान्त पन्द्रह वर्ष का अनुभव (पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने के लिए किए गए शोध कार्य की गणना कुल अनुभव में की जाएगी)।

## वॉछनीय अर्हता :-

1. न्यायालयिक प्रयोगशाला में कार्य करने का अनुभव।
2. हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान वशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं :- आयु: लागू नहीं।  
शैक्षिक अर्हता: लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :- (।) शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट आधार पर, दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा :- राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला के उप निदेशकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, निम्नलिखित द्वारा ;

सैकेण्डमेंट आधार पर स्थानान्तर :- भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय /राज्य न्यायालयिक प्रयोगशालाओं के अधिकारियों में से :-

(क) (1) सदृश पदधारक या 14,300—18,600 रुपये के समतुल्य वेतनमान के पदधारक में से।

(ii) 12000—15500 रुपये और 14300—18600 रुपये के वेतनमान या समतुल्य पदों में तीन वर्ष की सेवा वालों में से।

(ख) इन नियमों की स्तम्भ संख्या 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए ग्रेड में उनके सेवाकाल के आधार पर राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला के समस्त डिवीजनों की उनकी डिवीजनवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

**स्पष्टीकरण:-** अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

**12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना :-** जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:-** जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

**14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा :-** किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

**15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :-** सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

### **15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:-**

#### **(1). संकल्पना :-**

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, में निदेशक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आना:

सचिव (गृह), रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्षता को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

**(II) संविदात्मक उपलब्धिया :-** संविदा के आधार पर नियुक्त निदेशक, को 21,450 रुपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 400/-रुपए (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

**(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :-**सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

**(IV) चयन प्रक्रिया :-** संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

**(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:-** जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**VI. करार :-** अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

#### **VII. निबन्धन और शर्त :-**

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त निदेशक को 21,450/-रुपये की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 400/- रूपए की दर से (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।
- (ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
- (घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।
- (ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
- (ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

**(VIII)नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार :-** इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में निदेशक, के रूप में नियमितिकरण /स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

**16. आरक्षण :-** सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

**17. विभागीय परीक्षा :-** सेवा में प्रत्येक सदस्य को हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

**18. शिथिल करने की शक्ति :-** जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के

परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

### उपाबन्ध— "ख"

निदेशक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (पद का नाम) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री श्री.....  
.....निवासी.....संविदा पर नियुक्त  
व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.....को किया गया।

द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने निदेशक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार निदेशक के रूप में.....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (पर्यवसित) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.....रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त(पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त निदेशक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त निदेशक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त निदेशक कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे

अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

*[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-C(A)3-5/2006 dated 30-8-2007 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]*

## HOME DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2 the, 30-08-2007*

**No. Home-C(A)3-5/2006.—II** In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Director, Class-I (Gazetted) in State Forensic Science Laboratory, Home Department, Himachal Pradesh as per Annexure “A” attached to this notification namely:-

**1. Short title and commencement:—** (1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, State Forensic Science Laboratory, Home Department, Director, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007.



(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

**2. Repeal and Savings:—** (1) The State Forensic Science Laboratory Police Department, Himachal Pradesh, Director, Class-I (Gazetted) notified vide Notification No. Home-A(B)2-1/89 dated 8-5-1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the Rules, so repealed under Rule 2(1) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken under these Rules.

By order,  
S. VIJAY KUMAR,  
Principal Secretary.

#### Annexure-A

### **RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DIRECTOR, (CLASS-I GAZETTED), IN THE STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY, HOME DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH**

1. *Name of Post* : Director
2. *Number of Post* : 01 (One)
3. *Classification* : Class-I (Gazetted)
4. *Scale of Pay* : Rs.14300-400-15900-450-18600
5. *Whether Selection post or Non-Selection post* : Selection
6. *Age for direct recruitment* : Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in public sector Corporations /Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations /Autonomous Bodies shall be allowed, age concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the

Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations /Autonomous Bodies after initial constitution of the public Sector Corporations /Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for Inviting applications or notified to the employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relax able at the discretion of the H.P Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified

**7. Minimum educational qualification and other qualifications required for direct recruits:—**

**Essential Qualification: -**

- (I) At least 2<sup>nd</sup> class Master's Degree in Chemistry / Zoology / Botany / Physical Anthropology / Bio-Technology / Bio-Chemistry / Physics / Forensic Science / Mathematics / Pharmacy / Molecular Biology / Human Biology / Micro Biology / Human Genetics/ Pharmacology or equivalent from a recognized University.
- (II) 15 years post M.Sc. experience in research training and analytical work in one of the above or allied subjects (Research work done for doing Ph.D. Degree shall be counted in total experience.)

**Desirable qualification:—**

1. Experience of working in a Forensic Science Laboratory.
2. Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

**8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees:—** Age: Not applicable. Educational Not applicable. qualification:

**9. Period of Probation, if any:—** Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

**10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods:—**100 % by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment or on contract basis.

**11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ transfer is to be made:—** By promotion from amongst the Deputy Directors, State Forensic Science Laboratory with three years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which with prior consultation with H.P.P.S.C.

**TRANSFER ON SECONDMENT:—** Officers under Center/ State Forensic Science Laboratories in India.

- (a) (i) Holding analogous post or a post in equivalent scale of Rs.14300-18600.
- (ii) With three years service in the posts in the scale of Rs.12000-15500 and Rs.14300-18600 or equivalent
- (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Rules-7.

For the purpose of promotion a combined seniority list of all divisions of State Forensic Science Laboratory shall be prepared on the basis of their length of service in the grade without disturbing their division-wise inter-se-seniority.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

- (i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less.

Provided further that where a junior person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person (s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**EXPLANATION:—** The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-serviceman recruited under the provisions happened to be Ex-servicemen recruited under the provision of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc

service as referred to above shall remain unchanged.

**12. *If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?***

As may be constituted by the Government from time to time.

**13. *Circumstances under which the H.P. Public Service Commission to be consulted in making recruitment:***— As required under the law.

**14. *Essential requirements for a direct recruitment:***— A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

**15. *Selection for appointment to post by direct recruitment:***— Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority as the case may be, so considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus, etc, of which, will be determined by the Commission/other recruiting authority as the case may be.

**15-A. *Selection for appointment to the post by Contract appointment:***—

**(I) CONCEPT:**

(a) Under this policy, the Director in the State Forensic Science Laboratory of Home Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

(b) Post Falls Within The Purview of HP

**PUBLIC SERVICE COMMISSION:**— The Secretary (Home) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(d) Contract appointee so selected under these Rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government job.

**(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:**— The Director appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.21450/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale + Dearness pay). An amount of Rs.400/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.

**(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:**— The Secretary(Home), H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

**(IV) SELECTION PROCESS:**— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission.

**(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:—**

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.Public Service Commission from time to time.

**(VI) AGREEMENT:—** After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

**(VII) TERMS AND CONDITIONS:—**

- (a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.21,450/- per month (which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.400/- (equal to annual increase in the pay scale of the post) per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given.
- (b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.
- (d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement & LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- (e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
- (g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates, pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
- (h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular Officials at the minimum of the pay scale.

**(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:—** The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim for regularization/permanent absorption as Director in the Department at any stage.

**16. Reservation:—** The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

**17. Departmental Examination:—** Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1997.

**18. Powers to Relax:—** Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

## Annexure-B

**Form of contract/agreement to be executed between the Director, SFSL (Name of the post) and the Government of Himachal Pradesh through \_\_\_\_\_ (Designation of the Appointing Authority).**

This agreement is made on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ in the year \_\_\_\_\_ Between Sh./Smt. \_\_\_\_\_ S/o/D/o Shri \_\_\_\_\_ R/o \_\_\_\_\_

Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through \_\_\_\_\_ (Designation of the Appointing Authority) Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Director (Name of the post) on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Director (Name of the post) for a period of 1 year commencing on day of \_\_\_\_\_ and ending on the day of \_\_\_\_\_. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on \_\_\_\_\_. And information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. \_\_\_\_\_ per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.

5. Contractual Director (Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Director (Name of the post). He will not be entitled for Medical

Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

6. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Director (Name of the post) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

7. Transfer of an official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

8. Selected candidate will have to submit a certificate of his / her fitness from a Government / Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

9. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

**IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written**

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(Name and Full Address)

**कृषि विभाग**

शिमला-2, 17 सितम्बर, 2007

**संख्या एग्र. -ए (3) -6/2005.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में कृषि प्रसार अधिकारी, वर्ग—III [अराजपत्रित] के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-क के अनुसार भर्ती और पदोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— {1} इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, कृषि प्रसार अधिकारी, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती एवं पदोन्नति के नियम, 2007 हैं

{2} ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—{1} इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एग्र बी-3(6) / 76 दिनांक 15.9.95 द्वारा अधिसूचित और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या: एग्र बी (14)10 / 94 तारीख 29.12.98 द्वारा संशोधित हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, कृषि प्रसार अधिकारी [कृषि] वर्ग—III [अराजपत्रित] भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 1995 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

{2} ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप नियम {1} के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जायेगी।

आदेश द्वारा,  
हस्ता/-  
प्रधान सचिव।

कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश में कृषि प्रसार अधिकारी श्रेणी—III [अराजपत्रित] के भर्ती एवं पदोन्नति नियम।

1. पद का नाम	:	कृषि प्रसार अधिकारी
2. पदों की संख्या	:	978 [नौ सौ अठहत्तर]
3. वर्गीकरण	:	वर्ग—III [अराजपत्रित]
4. वेतनमान	:	4020.120.4260.140.4400.150.5000.160.5800 कृ200 6200 /— रुपये।
5. चयन पद अथवा अचयन पद	:	अचयन पद
6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु	:	18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में



नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगा; परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिये उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर/निगम तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जायेगी जो पश्चात्पूर्ति ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेसित किये गये हैं/किये गये थे।

(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना आयोग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रा प्राप्ति के अन्तिम दिन से की जायेगी।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकेगी।

## 7. सीधी भर्ती के लिए आपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:-

**अनिवार्य अर्हताएं:-**“जी0एस0टी0सी0/वी0ए0एस0 से कृषि में एक वर्ष के व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय सहित 10+2 या इसके समतुल्य”

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी0एस0सी[कृषि]की उपाधि उत्तीर्ण की हो या इसके समकक्ष।

**वांछनीय अर्हतायें:-**हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिये उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतायें प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं :-

I) आयु लागू नहीं

II) शैक्षणिक अर्हतायें: हों जैसी कि स्तम्भ संख्या-11 में विहित है।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:- दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिये विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद {पदों} की प्रतिशतता:-

(i) 90 प्रतिशत निम्न प्रकार से सीधी भर्ती द्वारा :-

{क} 45 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

{ख} 45 प्रतिशत विभाग द्वारा बैच वाईज नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर।

(ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर।

**11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणियां {ग्रेड} जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जायेगा.**—दस प्रतिशत प्रयोगशाला सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जो मैट्रिक स्तर की शैक्षणिक अर्हता रखते हों और जिनका 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वर्ग-4 कर्मचारियों में से जो विज्ञान विषय सहित मैट्रिक की शैक्षणिक अर्हतायें रखते हों और उन्हें विभाग द्वारा एक वर्ष का वी0ए0एस0 प्रशिक्षण दिया जायेगा/ दिया गया हो तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की, उनकी यूनिट-वार पारस्परिक वरिष्ठता को छोड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिये इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिये इस शर्त के अधीन रखते हुये गणना में ली जायेगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी : परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल {तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो} के आधार पर उपयुक्त, निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किये जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने अपने प्रवर्ग/पद /कॉडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किये जाने के पात्र समझे जायेंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखें जायेंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिनपर प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी:

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किये जाने सम्बन्धी विचार के लिये अपात्र हो जाता है वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिये अपात्र समझा जायेगा/ समझे जायेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिये अपात्र नहीं समझा जायेगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डेमोबीलाईज्ड आर्मड फोरसिस परसोनल { रिजर्वेशन आफ वकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज } रूल्ज, 1972 के नियम -3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों या जिसे एक्ससर्विसमैन {रिजर्वेशन ऑफ वकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज } रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिये गये हों।

{2} इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरण पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिये गणना में ली जायेगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी;

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:—जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा:—जैसा विधि द्वारा आपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अनिवार्य अपेक्षा:—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन:—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। यदि, यथा स्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझें तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।

#### 15. [क] संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

(I) संकल्पना:—[क] इस पॉलिसी के अधीन कृषि विभाग में कृषि प्रसार अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

[ख] पद क हि0प्र0 लोक सेवा आयोग/हि0प्र0 अधीनस्थ सेवाएँ चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना:—निदेशक, कृषि रिक्त पदों को संविदा आधार पर भरने हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हि0प्र0 अधीनस्थ सेवाएँ चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

[ग] चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

[घ] इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा[जॉब] में नियमितिकरण या स्थाई आमेसन का दावा करने, का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धिय :-संविदा के आधार पर नियुक्त कृषि प्रसार अधिकारी को 6030/- रु0 की दर से नियमित समेकित संविदात्मक रकम {जो वेतन के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी} प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक वर्ष की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 120/- रु0 वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी:— निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:—(क) विभागीय स्तर पर बैच वाईज भरे जाने वाले पद {दों} को भरने के लिए:—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इन नियमों के अधीन गठित चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ख) सम्बद्ध भर्ती अभिकरण के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए:—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन मौखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम

सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ट) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:—(क) विभागीय स्तर पर बैच वाईज भरे जाने वाले पदों के लिए:—“जैसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर गठित की जाए।”

(ख) सम्बद्ध भर्ती प्राधिकरण के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए:—“जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

**(VI) करार:—** अभ्यर्थी को चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

**(VII) निबन्धन और शर्तें:—**{क} संविदा के आधार पर नियुक्त कृषि प्रसार अधिकारी को 6030/—रु0 की दर से नियत समेकित संविदात्मक रकम { जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी } प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 120/— रु0 की प्रति वर्ष की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएँ जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

{ख} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किये जाने के लिए दायी होगी, यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है,।

{ग} संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

{घ} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

{ङ} नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति {पर्यावसान} हो जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य { ड्यूटी } से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

{च} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

{छ} चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

{ज} संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

**(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार:—**इन नियमों के अधीन संविदा के आधार

पर लगाए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में कृषि प्रसार अधिकारी के रूप में नियमितिकरण/स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

**16. आरक्षण:—**सेवा में नियुक्ति, हि0प्र0 सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये अनुदेशों के, अधीन होगी।

**17. विभागीय परीक्षा:—**लागू नहीं।

**18. शिथिल करने की शक्ति:—** जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां इन कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति [व्यक्तियों] के प्रवर्ग या पद [पदों] की बाबत शिथिल सकेगी।

उपाबन्ध(ख)

कृषि प्रसार अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक कृषि, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार कुमारी/श्री/श्रीमति.....  
पुत्रा/पुत्री श्री.....निवासी.....  
.....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति [जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है] और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य ..... के माध्य निदेशक कृषि, हि0प्र0 [जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है] के मध्य से आज तारीख ..... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कृषि प्रसार अधिकारी के रूप में संविदा आधार पर, निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार कृषि प्रसार अधिकारी के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और .....को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की, द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित [समाप्त] समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ..... रु0 प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक नियुक्ति प्रथम पक्षकार को किसी भी दशा में नियमितिकरण के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदात्मक कृषि प्रसार अधिकारी एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक कृषि

प्रसार अधिकारी को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान {समापन} हो जाएगा। संविदात्मक कृषि प्रसार अधिकारी कर्त्तव्य {ड्यूटी} से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि वेतनान के न्यूनतम पर नियमित प्रस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

10. संविदा नियुक्त व्यक्ति[यों] को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

{नाम व पूरा पता}

2.....

.....

{नाम व पूरा पता}

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....

{नाम व पूरा पता}

2.....

.....

{नाम व पूरा पता}

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

## नगर एवं ग्राम योजना विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 12 सितम्बर, 2007

**संख्या: टी0सी0पी0-एफ (5)-1/2006.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा-66की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या: टी0 सी0 पी0-एफ(5)-4/2000 तारीख 11-8-2000 द्वारा यथा अधिसूचित, नीचे यथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अपवर्जित करते हुए कण्डाघाट विशेष क्षेत्र की परिसीमाओं का परिवर्तन करते हैं:—

क्रम संख्या	राजस्व गाँव का नाम	हदबस्त संख्या:
	राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या: 22 के दोनो तरफ 100 मीटर निम्न राजस्व गाँवों से होते हुए:—	
	(i) शड़याल	399
	(ii) कैथली	425
	(iii) शुंगल	398
	(iv) दिहरी	424

उपरोक्त क्षेत्र के अपवर्जन के परिणामस्वरूप, कण्डाघाट विशेष क्षेत्र की पुनः परिभाषित परिसीमाएं निम्नलिखित होंगी :—

## कण्डाघाट विशेष क्षेत्र का विनिर्देश

1. सोलन योजना क्षेत्र की सीमा से सिरीनगर (कण्डाघाट) हदबस्त न0 441 तक राष्ट्रीय उच्चमार्ग संख्या-22 के दोनों तरफ 100 मीटर ।
2. सिरीनगर कण्डाघाट (हदबस्त न0 441)
3. सिरीनगर (कण्डाघाट) से राजस्व गाँव दिहारी (हदबस्त न0 424) की बाहरी सीमा तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या:22 के दोनो तरफ 100 मीटर ।

आदेश द्वारा  
हस्ता/-  
सचिव ।

[Authoritative English Text of Government Notification no. Tcp-f(5)-1/2006 dated 12-9-2007 as required under clause (3) of Article -348 of the constitution of India].

## TOWN &amp; COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Shimla-2, 12<sup>th</sup> September, 2007

**No. TCP-F(5)-1/2006.**— In exercise of the powers conferred by clause(a) Sub- Section (3) of Section-66 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to alter the limits of Kandaghat Special Area

by excluding the area as specified below and as notified vide Notification No. TCP-F(5)-4/2000 dated 11-8-2000.

Sr. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.
1.	100 Metre on both sides of National Highway No.22 passing through the revenue villages as under:— (i) Shadyal (ii) Kathli (iii) Shungal (iv) Dihari	399 425 398 424

Consequent upon exclusion of above area, the redefined limits of Kandaghat Special Area shall be as under:—

### **SPECIFICATION OF KANDAGHAT SPECIAL AREA**

1. 100 Metres on both side of National Highway No. 22 starting from the boundary of Solan Planning Area upto Siri Nagar (Kandaghat) Hadbast No. 441.
2. Siri Nagar (Kandaghat) Hadbast No. 441.
3. 100 Metre on both sides of National Highway No. 22 from Siri Nagar (Kandaghat) to the outer boundary of revenue village Dihari, Hadbast No. 424.

By order,  
Sd/-  
Secretary.

### **TOWN & COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

#### **NOTIFICATION**

*Shimla-2 the 25<sup>th</sup> August, 2007*

**No.TCP(E)1-5/2007(Estt.)CWP.**—The matter to identify posts to provide reservation to the disable persons in direct recruitment posts of town & Country Planning Department was reviewed in accordance with section 32 of Persons with Disability (Equal Opportunities, Protection of rights and full Participation) Act, 1995. the cateogory of persons whom the posts in direct recruitment can be reserved have been identified. Therefore, the Governor, Himachal Pradesh is



pleased to provide reservation to the disabled persons in direct recruitment posts of TCP Department as under:—

Sl. No.	Name of Post	Total No. of sanctioned Posts	Mode of rectt.	Category of Person with Disabilities for whom the posts can be reserved	Remarks
1.	Town & Country Planner	8	100% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment	1 Post for Locomotor's	Being field/public dealing job, reservation can not be extended to the other categories.
2.	Assistant Town Planner	14	50%by direct rectt. 50%by promotion	-do	-do
3.	Planning Officer	19	20%by direct rectt. 75%by promotion 5%by Transfer	-do	-do
4.	Senior Planning Draughtsman	13	50%by direct rectt. 50%by promotion	-do	-do
5.	Junior Engineer	29	100%direct rectt.	-do	-do
6	Draughtsman	5	80%by direct rectt. 20%by promotion	1 Post for hearing impairment/locomotor's	Due to nature of duty of the post, reservation can not be given to the blind person.
7.	Junior Draughtsman	10	80%by direct rectt. 20%by promotion	-do	-do
8.	Field Investigator	3	100% by direct rectt.	1 Post for locomotor's	Being field/public dealing job, reservation can not be given to the other categories.
9.	Ferro Printer	3	100% by promotion failing which on secondment basis failing both by direct recruitment or on contract basis	1 Post for Hearing impairment/locomotor's	Due to nature of duty of the post, reservation can not be given to the blind person.

10.	Steno-Typist	15	100% by direct rectt	1 Post for locomotor's	Due to nature of duty of the post, reservation
					can not be given to the
					blind and hearing
					impairment person.
11.	Clerk	27	90% by direct rectt.	1 Post for	Due to nature of duty
			10%by promotion	Hearing	of the post, reservation
				impairment/l	can not be given to the
				ocomotor's	blind person
12.	Peon	16	100% by direct rectt	1 Post for Hearing	Due to nature of duty of the post, reservation
				impairment/l	can not be given to the
				ocomotor's	blind person.
13.	Chowkidar-cum	7	100% by direct rectt	1 Post for locomotor's	Due to nature of duty of the post, reservation
	Sweeper				can not be given to the
					other categories.

By order,  
Sd/-  
Secretary.

**Proclamation under Order 5, Rule 20, C. P. C.**

**In the Court of Shri Arvind Kumar, Civil Judge (Jr. Division) Dehra, District Kangra (H. P.).**

Civil Suit No. 96/2006

Smt. Foolan Devi w/o Shri Kesri, r/o Mohal and Mouza Dhawala, Tehsil Dehra, District Kangra (H. P.) . . Plaintiff.

*versus*

1. Smt. Subh Lata w/o Shri Dalip Singh r/o Mohal Deyoldhu, Mouza Talahan Kalan, Tehsil Dehra, District Kangra (H. P.) . . Defendants.
2. Smt. Resha d/o Shri Shyamu r/o Mohal Dayoldhu, Mouza Talahan Kalan, Tehsil Dehra, District Kangra (H. P.).

Notice to.—Defendant No. 2

. . Defendants.

Whereas in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that above named defendant/defendants is/are avoiding service of summons and cannot be served in the ordinary way. Hence this proclamation is hereby issued against him/them to appear in this court on 29-9-2007 at 10.00 A. M. to defend the case personally or through an authorised agent or pleader failing which *ex-parte* proceedings will taken against him/them.

Given under my hand and the seal of the Court this 31<sup>st</sup> day of August, 2007.

Seal.

ARVIND KUMAR,  
Civil Judge (Jr. division) Dehra,  
District Kangra (H.P.).

न्यायालय श्री वी० एस० लगवाल, तहसीलदार कुल्लू एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

स्थानीय इशतहार

बनाम

आम जनता

श्री हरफू राम पुत्र श्री वीर चन्द, साकन पाहानाला, डाकघर खड़ीहार, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की कुमारी सुनीता का जन्म दिनांक 7-8-2002 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी लड़की के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण ग्राम पंचायत खड़ीहार के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु अब आवेदनकर्ता अपनी लड़की के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत खड़ीहार में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा ग्राम पंचायत खड़ीहार द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उसकी रिपोर्ट से पाया गया है कि कुमारी सुनीता का जन्म के इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कुमारी सुनीता के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत खड़ीहार में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इशतहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और कुमारी सुनीता के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत खड़ीहार के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 31-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

वी० एस० लगवाल,  
तहसीलदार कुल्लू एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

न्यायालय श्री वी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार कुल्लू एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

### स्थानीय इश्तहार

बनाम

आम जनता

श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री हिम्मत राम, साकन रुआडू, डाकघर पिपलाणे, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका अपना कन्हैया लाल का जन्म दिनांक 1-1-1953 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण ग्राम पंचायत नरैश के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु आवेदनकर्ता अपना अपना जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नरैश में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा ग्राम पंचायत नरैश द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई है। उसकी रिपोर्ट से पाया गया है कि श्री कन्हैया लाल के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री कन्हैया लाल के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नरैश में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और श्री कन्हैया लाल के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नरैश के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 31-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

वी0 एस0 लगवाल,  
तहसीलदार कुल्लू एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

न्यायालय श्री वी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार कुल्लू एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

### स्थानीय इश्तहार

बनाम

आम जनता

श्री होतम राम पुत्र श्री हिम चन्द, साकन नथान सेरी, डाकघर लरांकलो, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसके लड़के श्री मोहन लाल का जन्म दिनांक 5-1-2002 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपने लड़के के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण ग्राम पंचायत नथान के जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु आवेदनकर्ता अपना लड़के के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नथान में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू तथा ग्राम पंचायत नथान द्वारा प्राप्त की गई है। उसकी रिपोर्ट से पाया गया है कि श्री मोहन लाल के जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री मोहन लाल के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नथान में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और श्री मोहन लाल के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत नथान के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 31-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

वी0 एस0 लगवाल,  
तहसीलदार कुल्लू एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-----

न्यायालय श्री वी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार, कुल्लू, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

स्थानीय इश्तहार

बनाम

आम जनता

श्री सीता राम वर्मा पुत्र श्री धनी राम, साकन गड़सा रोड़ भून्तर, डाकघर भून्तर, तहसील व जिला कुल्लू ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसकी लड़की श्रीतिका का जन्म दिनांक 26-4-2005 को हुआ है। आवेदनकर्ता अपनी लड़की के जन्म का इन्द्राज पता न होने के कारण नगर पंचायत भून्तर में जन्म रजिस्टर में दर्ज न करवा पाया है। परन्तु आवेदनकर्ता अपनी लड़की के जन्म का इन्द्राज ग्राम पंचायत भून्तर में करवाना चाहता है। इस इन्द्राज बारे जिला पंजीकार, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कुल्लू तथा सचिव, नगर पंचायत भून्तर द्वारा रिपोर्टे प्राप्त की गई है। उनकी रिपोर्ट से पाया गया कि श्रीतिका का जन्म का इन्द्राज उनके रिकार्ड में न हुआ है।

अतः सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीतिका के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत भून्तर में दर्ज करने का एतराज हो तो वह किसी भी कार्य दिवस में इश्तहार साथ होने के एक महीने के अन्दर-अन्दर अपना उजर व एतराज असालतन या वकालतन इस कार्यालय में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा किसी का भी उजर व एतराज न होने की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जावेगी और श्रीतिका के जन्म का इन्द्राज नगर पंचायत भून्तर में जन्म रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 31-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर ।

वी0 एस0 लगवाल,  
तहसीलदार कुल्लू कार्यकारी दण्डाधिकारी  
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 सलाक्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 42/07 (रीडर)

श्री नूप राम पुत्र स्व0 श्री झुडा राम, गांव वीनण, फाटी कुंगश, कोठी जांजा, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश . प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण जनता

. प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नूप राम पुत्र स्व0 श्री झुडा राम, गांव वीनण, फाटी कुंगश, उप-तहसील आनी ने इस कार्यालय में एक दरखास्त के साथ शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माता की मृत्यु तिथि 19-12-1999 है जो ग्राम पंचायत कुंगश में दर्ज नहीं है जिसको प्रार्थी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कुंगश में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट द्वारा अपना एतराज अदालत में असालतन या वकालतन प्रस्तुत करें। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर उपरोक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत सम्बन्धित में दर्ज करने बारे आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पी0 सी0 सलाक्टा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 सलाक्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 34/07 (रीडर)

श्री भीम सैन पुत्र श्री मोतू राम, गांव गोथना, फाटी पलेही, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण जनता

. प्रत्यार्थी।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भीम सैन पुत्र श्री मोतू राम, गांव गोथना, फाटी पलेही, उप-तहसील आनी ने इस कार्यालय में एक दरखास्त के साथ शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 17-11-2001 है जो कि ग्राम पंचायत पलेही में दर्ज नहीं है को अब पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत पहेली में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अपना एतराज अदालत में असालतन या वकालतन प्रस्तुत करें। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत सम्बन्धित में दर्ज करने बारे आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।  
मोहर।

पी0 सी0 सलाक्टा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 सलाक्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 36 / 2007 (रीडर)

श्री जीवन लाल पुत्र श्री जालम राम, गांव कुंगश आरन, फाटी कुंगश, कोठी जांजा, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

सर्वसाधारण जनता

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जीवन लाल पुत्र श्री जालम राम गांव कुंगश आरन, फाटी कुंगश, कोठी जांजा, उप-तहसील आनी ने इस कार्यालय में एक दरखास्त के साथ शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र की जन्म तिथि 13-5-2005 है जो कि ग्राम पंचायत कुंगश में दर्ज नहीं है को अब पंचायत रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुंगश में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अदालत में असालतन या वकालतन प्रस्तुत करे। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत सम्बन्धित में दर्ज करने बारे आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पी0 सी0 सलाक्टा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री पी० सी० सलाक्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० 38/2007 (रीडर)

श्री बीरबल पुत्र श्री जगत राम, गांव रोपा फाटी शिलेहा, कोठी जांजा, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि० प्र०) . . प्रार्थी ।

बनाम

सर्वसाधारण जनता

. . प्रत्यार्थी ।

विषय.—दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बीरबल पुत्र श्री जगत राम गांव रोपा फाटी शिलेहा, उप-तहसील आनी ने इस कार्यालय में एक दरखास्त के साथ शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी गोद ली गई पुत्री सुहानी कुमारी की जन्म तिथि 3-1-2005 है जो ग्राम पंचायत रोपा में दर्ज नहीं है जिसको प्रार्थी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत रोपा में दर्ज करने बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अपना एतराज अदालत में असालतन या वकातलन प्रस्तुत करे। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत सम्बन्धित में दर्ज करने बारे आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक .....को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

पी० सी० सलाक्टा,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,  
आनी, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

-----  
ब अदालत श्री हरि सिंह ठाकुर, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

श्रीमती पुनी देवी पत्नी स्व० श्री गंगा राम, निवासी पंदलाही (बडवाहण), डा० उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि० प्र०) . . प्रार्थिन ।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी ।

भू-राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

श्रीमती पुनी देवी पत्नी स्व० श्री गंगा राम, निवासी पंदलाही (बडवाहण), डा० उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि० प्र०) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र व पंचायत रिकार्ड में पुनी देवी प्रविष्ट है। जो सही है। प्रार्थिन का घरेलू नाम कौशल्या देवी परिवार के सदस्यों द्वारा गलती से राजस्व विभाग में दर्ज करवाया गया है। जिससे प्रार्थिन को अब असुविधाओं का सामना करना



पड़ रहा है। प्रार्थिन ने इस अदालत में प्रार्थना की है कि राजस्व अभिलेख में उसका नाम कौशल्या देवी उर्फ पुनी देवी दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असागतन या वकलातन दिनांक 3-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में पेश करें। उपस्थित न होने की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र पर यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-8-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हरि सिंह ठाकुर,  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत श्री डी0 एस0 चन्देल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी कलैहणी, ई0 लोयर करसोग, जिला मण्डी . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बावत किए जाने नाम दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड।

श्री कृपाल सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी महाल कलथर, तहसील थुनाग हाल निवासी कलैहणी, ई0 लोयर करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड शिलीगाड, तहसील थुनाग में कृपाल सिंह है। परन्तु राजस्व रिकार्ड लोयर करसोग के अभिलेख में गोपाल सिंह है। जो कि गलत है इसलिए प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती चाही है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम दुरुस्ती में कोई एतराज हो तो वह दिनांक 18-10-2007 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असागतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 16-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

डी0 एस0 चन्देल,  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
करसोग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत श्री एस0 एल0 बंसल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री प्रकाश सिंह उपनाम प्रकाश चन्द पुत्र श्री धर्म चन्द, निवासी महाल बहल, ईलाका फतेपुर, तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, महाल बहल, ईलाका फतेपुर, तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना—पत्र बावत किए जाने दुरुस्ती नाम अन्दर कागजात माल।

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत में दिनांक 28-8-2007 को एक दरखास्त इस आशय से गुजारी है कि उस का नाम राजस्व अभिलेख में प्रकाश चन्द दर्ज है। जबकि उसे प्रकाश सिंह के नाम से जन साधारण में जाना व पहचाना जाता है। नाम की दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में दर्ज करना चाहता है जिस के लिए उक्त प्रार्थी ने नकल परिवार रजिस्टर, नकल जमावन्दी, छाया प्रति प्रमाण—पत्र दसवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा शपथ पत्र भी दरखास्त के साथ गुजार रखा है।

अतः इस अदालती इशतहार के माध्यम से आम जनता, सगे सम्बन्धियों तथा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी उपरोक्त के नाम को कागजात माल में प्रकाश चन्द उर्फ प्रकाश सिंह दर्ज किये जाने बारा किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2007 को अदालत में हाजर आकर अपना एतराज पेश करें। अन्यथा किसी का एतराज न होने की स्थिति में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाएगी तथा प्रार्थी के पक्ष में आवश्यक आदेश पारित कर दिये जावेंगे। बाद गुजरने मियाद कोई कार्यवाही काबिले समायत नहीं होगी।

आज दिनांक 31-8-2007 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

एस0 एल0 बंसल,  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
तहसील थुनाग, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

-----

न्यायालय सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री बलदेव पुत्र श्री नेक राम, निवासी जुकैन, डा0 नवाही, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।  
. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में मृत्यु दर्ज करने बारे।

श्री बलदेव पुत्र नेक राम, निवासी जुकैन ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसकी माता की मृत्यु 26-9-2006 को हुई है। परन्तु पंचायत रिकार्ड में उसकी माता की मृत्यु दर्ज नहीं है। प्रार्थी उसे दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त मृत्यु पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 5-10-2007 को प्रातः दस बजे पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 16-08-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सरकाघाट,  
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

न्यायालय सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री शंकर दास उर्फ दया जीत पुत्र श्री सीता राम, निवासी तलाव, ई0 सुरांग, तहसील सरकाघाट,  
जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

श्री शंकर दास उर्फ दया जीत पुत्र श्री सीता राम ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में व पंचायत रिकार्ड में दयाजीत सिंह है। परन्तु स्कूल प्रमाण पत्र में उसका नाम शंकर दास दर्ज है। प्रार्थी पंचायत रिकार्ड में व राजस्व रिकार्ड में शंकर दास उर्फ दयाजीत सिंह करवाना चाहता है। अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारे कोई उजर हो तो वह तिथि 16-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जायेग

आज दिनांक 6-08-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सरकाघाट,  
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

न्यायालय सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री हिरा पुत्र श्री दुर्गा, r/o जवोठ, ईलाका वैरा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—नाम दुरुस्ती

श्री हिरा राम पुत्र दुर्गा गांव जवोठ ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया कि उसका नाम हिरा राम है परन्तु राजस्व रिकार्ड मुहाल जवोठ में उसका नाम गलती से बालक राम दर्ज है। अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारे कोई एतराज हो तो

वह असालतन या वकालतन दिनांक 16-10-2007 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकते हैं। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 23-08-2007 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सरकाघाट,  
जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

## MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

### NOTIFICATIONS

*Shimla-171002, the 18th September, 2007*

**No. Health-B(1)1/2007.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of 16 posts i.e. 8 posts of Associate Professors and 8 posts of Assistant Professors and upgradation of 2 posts of Assistant Professor (Pathology & Physiology) to that of Associate Professor in the following departments/specialities in IGM, Shimla in Medical Education department to met the MCI requirement for PG courses and 100 annual admissions for MBBS courses:-

Sr.No.	Name of post	No. of post	Faculty	Pay-scale
1.	Asso.Professor	1	Anatomy	Rs.16350-20100+400SA
2.	Asso. Professor	1	Forensic Medicine	..do...
3.	Asso.Professor	2	General Medicine	..do...
4.	Asso.Professor	1	Microbiology	..do..
5.	Asso. Professor	1	Pharmacology	..do...
6.	Asso. Professor	1*	Pathology	...do..
7.	Asso. Professor	1*	Physiology	...do...
8.	Asso.Professor	1	Community Medicine	...do..
9.	Asso.Professor	1	General Surgery	...do..
10.	Asstt. Professor	1	Forensic Medicine	Rs.16350-20100
11.	Asstt. Professor	2	General Medicine	...do..
12.	Asstt. Professor	1	Radiology	...do..
13.	Asstt. Professor	1	Radiotherapy	...do..
14.	Asstt. Professor	3	General Surgery	...do..

\*Two posts of Assistant Professor one each in the department of Pathology and Physiology are upgraded to that of Associate Professor in IGM, Shimla out of sanctioned post of Assistant Professors in IGM, Shimla in the pay scale of Rs. Rs.16350-20100+ 400 Special Allowance.

The expenditure on this account is debit able to Major Head “2210- Medical & Public Health, 105-Allopathy-05-Medical Education & Research, 01-IGM, Shimla (Non-Plan) under SOE Salary.

The concurrence of the Finance Department has been obtained vide their U.O. No. 50512960-Fin-F/2007 dated 27.8.2007.

*Shimla-171002, the 19th September, 2007*

**No. Health-B(B) 2-1/2001-II-loose.**—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of four supernumerary posts of Lecturers in following specialities /departments in the pay scale of Rs.7880-13500/- initial start of Rs.8000/-PM without NPA in Dr. RPGMC Kangra at Tanda in Medical Education department to regularize the services of the incumbents working on adhoc basis:-

Sr.No.	Faculty	No. of post
1.	Microbiology	2
2.	Bio-Chemistry	1
3.	Bio-Physics	1

The expenditure on this account is debit able to Major Head 2210 Medical & Public Health, 105-Allopathy-05-Medical Education & Research- 06 Dr. Rajinder Prasad Medical College ,Tanda (Plan) under SOE Salary.The regularization of incumbents will be made only after recommendation of Screening Committee constituted for this purpose.

The concurrence of the Finance Department has been obtained vide their U.O. No. 50507004-Fin-F/2007 dated 21.8.2007.

By order,  
Sd/-  
*Principal Secretary.*

-----

**HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**

**NOTIFICATION**

*Shimla, the 14th September, 2007*

**No.HHC/Estt.3 (117)/78-I.**— In partial modification of this Registry Notification of even number dated 1.9.2007, 8 days un-availed earned leave w.e.f. 8.9.2007 to 15.9.2007 is hereby cancelled in favour of Shri Tek Ram, Secretary of this Registry.

By order,  
Sd/-  
*Registrar General.*

**पंचायती राज विभाग****अधिसूचना**

शिमला-9, 10 सितम्बर, 2007

**संख्या:पी.सी.एच.-एच.ए.(3)4/96.-** क्योंकि श्रीमति राजकुमारी, सदस्य, जिला परिषद, मण्डी, वार्ड न0-31 (धनियारा) की नियुक्ति 24 अगस्त, 2007 को कनिष्ठ बेसिक अध्यापक के पद पर हो गई है और उन्होंने जिला परिषद मण्डी वार्ड न0-31 के सदस्य के पद से लिखित रूप से अपना त्यागपत्र परिदत् किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 135 के उप नियम (4) के अर्न्तगत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं राकेश कौशल, निदेशक पंचायती राज, श्रीमती राज कुमारी, सदस्य जिला परिषद मण्डी का वार्ड न0-31 (धनियारा) के सदस्य के पद से त्याग पत्र स्वीकृत करता हूँ और यह भी विनिश्चय करता हूँ कि यह त्याग पत्र दिनांक 30 अगस्त, 2007 से 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रभावी होगा और जिला परिषद, मण्डी के वार्ड न0-31 (धनियारा), के सदस्य के स्थान में आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी, यदि इसके प्रभावी होने से पूर्व उक्त श्रीमति राजकुमारी राणा अपने त्यागपत्र को अधोहस्ताक्षरी से अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में वापिस नहीं लेती हैं।

आदेश द्वारा,  
हस्ता/-  
निदेशक पंचायती राज।

**पंचायती राज विभाग****अधिसूचना**

शिमला-171 009, 28 अगस्त, 2007

**संख्या-पीसीएच-एचए(3)15/2007.-**क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश की याचिका संख्या 224/2007 'श्री धनवीर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य' में दिनांक 15 जून, 2007 में यह आदेश दिए हैं कि ग्राम पंचायत नधेता, विकास खण्ड पांवटा, जिला सिरमौर का मुख्यालय स्थान भाईला में रहेगा जहां से ग्राम पंचायत नधेता कार्य करती रहेगी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा की ग्राम सभा नधेता के मुख्यालय को 'नधेता' से बदलकर 'भाईला' में स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, उक्त बारे सूझावों आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं ;

यदि ग्राम सभा नधेता के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे ; राज्य सरकार, जिला सिरमौर, विकास खण्ड पांवटा की ग्राम सभा नधेता के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा,  
हस्ता/-  
सचिव।

**पंचायती राज विभाग****अधिसूचना**

शिमला-171 009, 10 सितम्बर, 2007

**संख्या—पी.सी.एच.—एच.ए.(3)2/2000-11.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पी0सी0एच0—एच0ए0(3)1/94-19181-362, तारीख 25 नवम्बर, 1997, द्वारा राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 25 नवम्बर, 1997 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं, और इन्हें जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश, में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है;

इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित कोई व्यक्ति, यदि उक्त नियमों के बारे में कोई आक्षेप/सुझाव देना चाहे तो वह उसे/उन्हें सचिव (पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002 को, प्रस्तावित संशोधनों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर भेज सकेगा;

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों), या सुझाव(वों), यदि कोई हों, पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

**प्रारूप नियम**

**1. संक्षिप्त नाम.**— इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) संशोधन नियम, 2007 है।

**2. नियम 21 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 21 के उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(6) विवाह रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त ग्राम पंचायत का अधिकारी या कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 तथा हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 के उपबन्धों के अनुसार विवाहों का रजिस्ट्रीकरण करेगा।”

**3 नियम 127 का संशोधन.**—उक्त नियमों के नियम 127 में,—

(i) शीर्षक में “या उप-प्रधान” शब्द और चिन्ह का लोप किया जाएगा ;

(ii) उप-धारा (1) में और श्या उप-प्रधान या दोनों शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा ;

(iii) उप-नियम (3) का लोप किया जाएगा ;

(iv) उप-नियम (4) में श्यथास्थिति या प्रधान, शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा ; और

(v) उप-नियम (8) में श्यथास्थिति या उप-प्रधान शब्दों और चिन्ह का लोप किया जाएगा।

#### 4. नियम 127-क का अन्तःस्थापन.—

उप-प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव[धारा 129(1-क)].—

(1) उप-प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित संकल्प लाने के आशय का नोटिस, उसके कारण देते हुए ग्राम पंचायत के किसी भी सदस्य द्वारा वैयक्तिक रूप से खण्ड विकास अधिकारी को परिदत्त किया जाएगा। उप-प्रधान के विरुद्ध लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की प्राप्ति पर, खण्ड विकास अधिकारी उस पर उक्त नोटिस की एक प्रति की तामील करेगा।

(2) खण्ड विकास अधिकारी ग्राम पंचायत के प्रधान को भी अविश्वास नोटिस की एक प्रति उसकी अध्यक्षता के अधीन ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के निदेश सहित, भेजेगा।

(3) खण्ड विकास अधिकारी से निदेशों की प्राप्ति पर, प्रधान, प्रस्ताव पर विचार करने के लिए ऐसे निदेशों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर ग्राम पंचायत की बैठक ऐसी तारीख और समय पर बुलाएगा जो उसके द्वारा नियत किया जाए :

परन्तु प्रधान के पद की आक्स्मिक रिक्ति की दशा में, प्रस्ताव पर विचार के लिए बैठक, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर उप-नियम (1) के अधीन बुलाई जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि प्रधान इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैठक बुलाने में असफल रहता है, तो यथास्थिति ग्राम पंचायत के, समस्त या कोई भी सदस्य जिन्होंने/जिसने उप-नियम (1) के अधीन संकल्प लाने के आशय का नोटिस दिया था, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित करने हेतु निवेदन करते हुए खण्ड विकास अधिकारी को लिखित रूप में सूचित करेंगे/करेगा। खण्ड विकास अधिकारी ऐसे निवेदन की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर प्रस्ताव पर विचार के लिए ऐसी तारीख और समय जो उसके द्वारा नियत किया जाए पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा।

(4) ग्राम पंचायत की बैठक की तारीख और समय पर, यथास्थिति, प्रधान या खण्ड विकास अधिकारी, अधिनियम की धारा 129 की उप-धारा (1-क) के अधीन यथा अपेक्षित ग्राम पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों की तीन-चौथाई गणपूर्ति सुनिश्चित करेगा, तथा तत्पश्चात् वह उसके द्वारा प्राप्त अध्यपेक्षा में नोटिस के पाठ को ग्राम पंचायत को पढ़कर सुनाएगा और प्रस्ताव लाने तथा उस पर चर्चा करने के लिए अनुज्ञात करेगा। चर्चा की समाप्ति पर और उप-प्रधान को उसके विरुद्ध प्रस्तावित हटाए जाने के विरुद्ध कारण बताने हेतु उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा :

परन्तु यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात् दो घण्टे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती, तो बैठक विघटित हो जाएगी तथा प्रस्ताव विफल समझा जाएगा।

(5) बैठक का अध्यक्ष प्रस्ताव के गुणागुणों पर नहीं बोलेगा और न ही वह उस पर मतदान करने का हकदार होगा।

(6) बैठक का अध्यक्ष मतदान का परिणाम घोषित करेगा। प्रस्ताव ग्राम पंचायत के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया गया है, तो उसे पारित समझा जाएगा।

(7) बैठक की कार्यवाही सचिव द्वारा अभिलिखित की जाएगी और वह उसकी एक प्रति, प्रस्ताव की प्रति और मतदान के परिणाम के साथ संबंधित खण्ड विकास अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी और उपायुक्त को भेजेगा।



(8) जहां प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो उप-प्रधान को उसके पद से तत्काल प्रभाव से हटाया गया समझा जाएगा, और, यथास्थिति, प्रधान या खण्ड विकास अधिकारी इस प्रभाव का नोटिस ग्राम पंचायत के कार्यालय पर चिपकवाएगा तथा उसकी एक प्रति की तामील हटाए गए उप-प्रधान पर करेगा।

आदेश द्वारा,  
हस्ता/—  
सचिव ।

-----  
[Authoritative English text of this Department Notification NO. PCH-HA(3)2/2000-II, dated 10th September, 2007 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

## **PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT**

*Shimla-171 009, the 10th September, 2007*

**NO. PCH-HA(3)2/2000-II.**— In exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994(Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh, proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997, published in Rajpatra Himachal Pradesh, Extra-ordinary, dated the 25th November, 1997 vide notification No. PCH-HA (3)1/94-19181-362 dated 25th November, 1997, and the same are hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) for the information of the general public;

If any person likely to be affected by the draft rules has any objection(s)/ suggestions(s) to make with regard to the said rules, he may send the same to the Secretary(Panchayati Raj) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002, within a period of thirty days from the date of publication of the proposed amendments in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

The objections(s) or suggestions(s), if any, received within the period specified above shall be taken into consideration by the State government before finalizing these rules, namely:-

### **DRAFT RULES**

**1. Short title.**—These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Amendment Rules, 2007.

**2 Amendment of rule 2.**—In rule 21 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Rules, 1997 (hereinafter refer to as the „said rules”), for sub-rule (6), the following shall be substituted, namely:-

“(6) The officer or employee of the Gram Panchayat, appointed as Registrar of Marriages, shall undertake registration of marriages in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Registration of Marriages Act, 1996 and the Himachal Pradesh Registration of Marriages Rules, 2004.”

**3. Amendment of rule 127.**— In rule 127 of the said rules,-

- (i) in heading, the words and sign “or Up-Pradhan” shall be deleted;
- (ii) in sub-section(1), the words and sign “or Up-Pradhan or both” shall be deleted ;
- iii) Sub-rule(3) shall be omitted ;
- (iv) In sub-rule (4), the words and sign “or the Pradhan, as the case may be,” shall be deleted; and
- (v) In sub-rule (8), the words and sign “or Up-Pradhan, as the case may be” shall be deleted.

**4. Insertion of rule 127-A.—**

No confidence motion against Up-Pradhan {Section 129 (1-A)}.-

(1) A notice of intention to move a resolution signed by not less than majority of the total elected members of the Gram Panchayat for bringing no confidence motion against the Up-Pradhan, giving reasons for the same, shall be delivered in person by any member of the Gram Panchayat to the Block development Officer. On receipt of the notice of no confidence to be brought against the Up-Pradhan, the Block Development Officer shall serve him with a copy of the said notice.

(2) The Block Development Officer shall also send a copy of the no confidence notice to the Pradhan of the Gram Panchayat with the direction to call a Gram Panchayat meeting under his Chairmanship.

(3) On receipt of the directions from the Block Development Officer, the Pradhan shall convene a meeting of the Gram Panchayat within a period of 15 days from the date of receipt of such directions for the consideration of the motion at such date and time as may be appointed by him:

Provided that in the event of casual vacancy in the office of the Pradhan, the meeting for the consideration of the motion shall be convened by the Block Development Officer within 15 days from the date of receipt of the notice under sub-rule(1):

Provided further that if the Pradhan fails to call a meeting within the period specified in this sub-rule, all or any of members of the Gram Panchayat, as the case may be, who had given notice of the intention to move a resolution under sub-rule (1) shall inform the Block Development Officer in writing requesting him to convene a meeting of the Gram Panchayat for consideration of no confidence motion. The Block Development Officer shall within 15 days of the receipt of such request, convene a meeting of the Gram Panchayat for the consideration of the motion at such date and time as may be appointed by him.

(4) On the date and time of the Gram Panchayat meeting, the Pradhan or Block Development Officer, as the case may be, shall ensure the quorum of three-fourth of the total elected members of the Gram Panchayat as required under sub-section(1-A) of section 129 of the Act, and then read out to the Gram Panchayat the text of the notice in the requisition received by him and shall allow the motion to be moved and discussed. Upon conclusion of the discussion and after a reasonable opportunity has been given to the Up-Pradhan to show cause against his proposed removal, the motion shall be put to vote:

Provided that if within two hours after the time appointed for meeting, the quorum is not present, the meeting shall stand dissolved and motion shall be deemed to have been defeated.

(5) The Chairman of the meeting shall not speak on the merits of the motion nor shall he be entitled to vote thereon.

(6) The Chairman of the meeting shall declare the result of the voting. The motion shall be deemed to have carried when it has been passed by a majority of two-thirds of the members of Gram Panchayat present and voting.

(7) The proceeding of the meeting shall be recorded by the Secretary and he shall send a copy of the same together with a copy of motion and the result of the voting to the Block Development Officer, District Panchayat Officer and to the Deputy Commissioner concerned.

(8) Where the motion has been carried, the Up-Pradhan shall stand removed from his office with immediate effect and the Pradhan or the Block Development Officer, as the case may be, shall cause a notice to this effect to be affixed at the office of the Gram Panchayat and serve a copy of the same to the removed Up-Pradhan.

By order,  
Sd/-  
Secretary.

## लोक निर्माण विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 2 अगस्त, 2007

**सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0) एफ(5) -226 / 2007.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव थाना कलौ, तहसील वंगाणा, जिला ऊना में ऊना-अग्धार-मण्डी राज्य उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग उ0 क्षेत्र कांगडा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

5. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी लोक निर्माण विभाग उ0 क्षेत्र कांगडा कार्यालय में किया जा सकता है।

## विवरणी

जिला ऊना	तहसील वंगाणा	गांव थाना कलौ	खसरा न०	रकबा (हेक्टेयर में)
			314 / 1 / 1	0-00-30
			321	0-01-80
			322	0-01-62
			323	0-00-80
			324	0-02-58
			325	0-02-44
			326	0-00-16
			343	0-06-54
			344 / 1	0-01-32
			345 / 1	0-00-03
			375 / 1	0-00-58
			376 / 1	0-00-30
			377 / 1	0-00-10
			378 / 1	0-00-12
			379 / 1	0-00-12
			539 / 1	0-01-23
			540	0-01-17
			541 / 1	0-00-22
			1388 / 545 / 1	0-00-09
			598	0-02-97
			543 / 1	0-00-39
			1390 / 599 / 1	0-00-40
			1391 / 599 / 1	0-01-50
			743 / 1	0-00-08
			744 / 1	0-00-24
			745 / 1	0-00-16
			746 / 1	0-00-08
			747 / 1 / 1	0-00-08
			747 / 2 / 1	0-00-08
			749 / 1	0-00-42
			756 / 1	0-00-40
			757 / 1	0-00-05
			1407 / 943 / 1 / 3 / 1	0-00-27
			1408 / 943 / 1	0-00-20
			1407 / 943 / 1 / 2 / 1	0-00-24
			1407 / 943 / 1 / 1 / 1 / 1	0-00-04
			945 / 1 / 1	0-00-12
			967	0-00-20
			969	0-00-08
			978	0-00-28
			981	0-00-57
			983	0-00-65
			984	0-00-77
			1001	0-00-24
			1002	0-00-72
			1004	0-00-45
			1005	0-04-94
			1006	0-00-93
			1007	0-01-40
			1377 / 1033 / 1	0-00-09
			1377 / 1033 / 2	0-00-06
			1377 / 1333 / 3	0-00-45
			1033 / 1	0-00-56
			1035 / 1	0-00-24
			1036 / 1	0-00-12

			1037	0-00-32
			1040 / 1 / 1	0-00-80
			1040 / 2 / 1	0-01-36
			1041 / 1	0-01-37
			1050	0-00-77
			1056	0-00-52
			1057	0-00-28
			1058	0-00-22
			1060	0-02-24
			1061	0-01-47
			1062	0-00-90
			1063	0-00-50
			1070 / 1	0-03-07
			1078 / 1	0-03-18
			1079	0-00-60
			1080	0-00-58
			1083	0-01-17
			1086	0-01-70
			1087	0-02-12
			1094	0-05-11
			1096	0-04-21
			1269 / 1	0-00-56
			944 / 1	0-00-13
			<u>किता : 78</u>	<u>0-75-17</u>

आदेश द्वारा,  
हस्ता/-  
प्रधान सचिव।

## लोक निर्माण विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 2 अगस्त, 2007

**सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 221 / 2007.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लमलैहडी, तहसील ऊना, जिला ऊना में ऊना- अग्धार- मण्डी राज्य उच्च मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग उ० क्षेत्र कांगडा (हि० प्र०) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नं०	रकबा (हैक्टरो में)
ऊना	ऊना	लमलैहडी	1688 / 2 / 3 / 1	0-02-56
		कुल जोड़	किता-1	0-02-56

आदेश द्वारा,  
हस्ता /—  
प्रधान सचिव।

### लोक निर्माण विभाग

#### अधिसूचना

शिमला-2, 3 अगस्त, 2007

**सं०पी०बी०डब्ल्यू०(बी०)एफ०—(5) 263 / 2007.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव गुम्मा तथा पोहल, तहसील कोटखाई, जिला शिमला में गुम्मा बखलों सड़क भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड शिमला के समक्ष लिखित आपत्ति दायर कर सकता है।

## विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा —बिस्वा
शिमला	कोटखाई	गुम्मा	304	5—11
			305	0—4
			306	10—4
			307 / 2	6—9
			310	0—2
			311	1—9
			911 / 393 / 2	0—2
			913 / 393 / 2	0—10
			912 / 393 / 2	0—8
			348	0—3
			234 / 2	2—14
			235 / 1	1—0
			236	0—5
			241	4—13
			243	5—2
			248	0—2
			250	0—7
			258	3—10
			259	0—4
			262	0—11
			264	0—2
			265	7—4
			267	0—5
			862 / 233	1—17
			193	0—3
			252	0—18
			253	2—13
			254	3—4
			263	0—2
			263 / 1	1—3
			266	3—1
			268	2—5
			240	2—0
			312 / 2	1—8
			313	0—15
			314	1—7
			396 / 2	0—8
		कुल जोड़	किता—37	72—05

जिला शिमला	तहसील कोटखाई	गांव पोहल	खसरा नम्बर	बीघा —बिस्वा
			78	2-11
			427 / 48	4-4
			430 / 49	5-17
			47	0-3
			170	3-7
			437 / 197	1-8
			66	4-14
			67	1-11
			444 / 333	2-0
			212	2-9
			330	1-19
			445 / 333	1-0
			119	1-6
			73	1-1
			76	3-17
			77	0-1
			465 / 83	0-6
			123	3-12
			164	0-18
			196	0-6
			201	8-12
			124	2-9
			136	11-1
			146	2-16
			23	0-6
			24	2-10
			25	0-7
			29	7-6
			37	4-5
			38	1-5
			39	1-1
			5	15-17
			26	1-15
			28	7-14
			42	0-15
			44	2-5
			236	1-3
			280	5-15
			266	5-0
			317	1-15
			320	0-14
			274	1-13
			502 / 276	0-9
			501 / 276	3-4
			283	1-17
			125	0-2
			211	1-17
			113	4-0
			114	0-1
			115	0-1
			144	3-2
			267	4-11
			373	1-1
			355	12-12
			279	6-15
			316	4-4
			260	3-1



			354	1-13
			349	2-18
			465 / 343	1-9
			482 / 348	1-9
			256	2-10
			269	0-14
			271	0-4
			339	0-15
			481 / 348	2-12
			237	2-0
			238	0-13
			239	1-1
			240	1-8
			272	1-0
			282	1-4
			268	1-11
			270	1-0
			272	1-0
			273	1-13
			346	2-4
			353	4-4
			41	0-9
			145	2-12
			468 / 112	1-9
			117	0-3
			118	0-11
		कुल जोड़ . .	110	2-17
			172	1-16
			166	0-7
			370	3-13
			371	0-11
			372	2-3
			452 / 374	7-0
			379	0-9
			380	2-15
			381	1-6
			478 / 348	1-2
			477 / 348	0-11
			किता-95	238-7

आदेश द्वारा,  
हस्ता/-  
प्रधान सचिव ।

-----  
योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 अगस्त, 2007

संख्या:पी0एल0जी0एफसी(एफ)1-9/94-540-खण्ड-V.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार रेलवे विभाग के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव प्रतापनगर, तहसील अम्ब, जिला ऊना में नंगल-तलवाड़ा रेल लाईन (चुरूडु-टकारला से अम्ब-अन्दौरा तक)

के निर्माण के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है । अतएव एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विस्तृत विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना के लिए घोषणा की जाती है तथा उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू अर्जन समाहर्ता (नंगल-तलवाड़ा रेलवे लाईन) सहायक आयुक्त, जिला ऊना को उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का एतद द्वारा निर्देश दिया जाता है ।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता (नंगल तलवाड़ा रेलवे लाईन) (सहायक आयुक्त, जिला ऊना), हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है ।

### विस्तृत विवरणी

	तहसील	गांव	खसरा न0	रकबा (हैक्टेयर)
ऊना	अम्ब	प्रतापनगर	843	0.22.10

आदेश द्वारा,

हस्ता/—  
सचिव ।